IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 13, April 2026
Impact Factor: 8.2

वित्तीय समावेशन से महिलाओं के आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण में जीविका (JEEViKA) की भूमिका: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ प्रिया

अतिथि सहायक प्राध्यापक,

ति० मां० भा० विश्वविद्यालय, (भागलपुर)

Email: rajib.sharma3@gmail.com

1. सारांश / Abstract

विकास अर्थशास्त्र में समावेशी विकास (Inclusive Growth) का मूल आधार वित्तीय समावेशन है। वित्तीय समावेशन ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए एक आवश्यक उपाय बन गया है। Bihar Rural Livelihoods Project, जिसे 2006 में बिहार सरकार ने शुरू किया था, जीविका (JEEViKA) ने ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं, माइक्रोफाइनेंस और सामुदायिक निवेश निधि से जोड़कर उनके जीवन-स्तर में काफी बदलाव लाया है। प्रस्तुत शोध-पत्र द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक अध्ययन है, जिसमें NABARD, World Bank, Ministry of Rural Development, NITI Aayog, RBI तथा Government of Bihar के प्रतिवेदनों का उपयोग किया गया है। इस अध्ययन के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं: (i) वित्तीय समावेशन की अवधारणा एवं ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी भूमिका का विश्लेषण, (ii) जीविका कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का मूल्यांकन, तथा (iii) वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं निर्णय-निर्माण क्षमता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। शोध के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि जीविका कार्यक्रम ने बिहार में 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों की स्थापना, ग्रामीण महिलाओं की बचत एवं ऋण-पहुँच में वृद्धि, आजीविका संवर्धन तथा ग्राम पंचायतों में महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यह शोध नीति-

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 13, April 2026 Impact Factor: 8.2

निर्माताओं को वित्तीय समावेशन आधारित सशक्तिकरण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा प्रदान करता है।

मुख्य शब्द (Keywords): *वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण, जीविका, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण बिहार*

2. प्रस्तावना / Introduction

भारत में महिलाओं का आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण देश के समग्र विकास का अहम हिस्सा बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से लक्ष्य संख्या 5 (लैंगिक समानता) और संख्या 8 (सम्मानजनक कामकाज और आर्थिक विकास) महिलाओं के वित्तीय समावेशन को विकास का अनिवार्य आधार मानते हैं (United Nations, 2015)। बावजूद इसके, भारत में बहुत सी ग्रामीण महिलाएं अभी भी बैंकिंग सेवाओं से दूर हैं; RBI (2022) के अनुसार, देश में महिलाओं के खाते पुरुषों की तुलना में करीब 20 प्रतिशत कम पहुंच पाते हैं। बिहार, जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला और मानव विकास सूचकांक में भी नीचले स्तर का राज्य है, वहाँ महिला साक्षरता, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी अभी भी बहुत पीछे हैं (NITI Aayog, 2021)। इस संदर्भ में, बिहार सरकार ने 2006 में विश्व बैंक की सहायता से जिविका परियोजना की शुरुआत की, जो अब तक का सबसे बड़ा महिला केंद्रित ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम बन चुका है (Government of Bihar, 2023)। जिविका का मूल मानना है कि वित्तीय संसाधनों तक आसान पहुंच महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाती है। यह शोध इस सवाल का जवाब खोजता है कि जिविका कार्यक्रम ने कितनी हद तक बिहार की ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय समावेशन के जरिये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में मदद की है। इस अध्ययन में मुख्य रूप से द्वितीयक आंकड़ों, नीति दस्तावेजों और अकादमिक साहित्य का विश्लेषण किया गया है।

3. वैचारिक ढाँचा / Conceptual Framework

3.1 वित्तीय समावेशन की अवधारणा

विश्व बैंक (2021) के अनुसार, वित्तीय समावेशन का मतलब है — हर व्यक्ति और व्यवसाय को उसकी जरूरत के मुताबिक आसान और सस्ती कीमत पर अच्छे वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ मिलें। RBI (2008) कहता है कि वित्तीय समावेशन, कमजोर वर्ग के लोगों तक कम खर्च में वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने की प्रक्रिया है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 13, April 2026 Impact Factor: 8.2

NABARD (2022) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन के लिए सबसे असरदार तरीका "स्वयं सहायता समूह–बैंक लिंक" (SHG-BLP) मॉडल रहा है। Rangarajan समिति (2008) ने वित्तीय समावेशन के चार हिस्से बताए: (i) ऋण या लोन की सुविधा, (ii) बचत का विकल्प, (iii) बीमा और (iv) भुगतान से जुड़ी सेवाएँ। ये चारों चीजें रोज़मर्रा की आजीविका में सीधा असर डालती हैं (Ministry of Rural Development, 2022)।

3.2 महिला सशक्तिकरण की अवधारणा

महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समान अधिकार, अवसर और स्वतंत्रता देना महिला सशक्तिकरण है। यह सिर्फ अधिकार देने तक सीमित नहीं है; यह उन्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता भी देना है। महिलाओं को सशक्तिकरण देने से वे स्वतंत्र हो जाती हैं और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकती हैं। इसके मुख्य आधार हैं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और कानूनी जागरूकता। शक्तिशाली महिलाएं परिवार, समाज और देश का समग्र विकास कर सकती हैं। इसलिए, एक प्रगतिशील और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए महिला सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है। Sen, A. (1999).

Kabeer (1999) के अनुसार महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में तीन आयाम सम्मिलित हैं: संसाधनों तक पहुँच (Access), एजेंसी (Agency) तथा उपलब्धियाँ (Achievements)। Sen (1999) ने महिला-विकास को 'क्षमता-विस्तार' (Capability Expansion) के रूप में परिभाषित किया, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता राजनीतिक भागीदारी की पूर्वशर्त है। NITI Aayog (2020) भी स्वीकार करता है कि वित्तीय समावेशन महिलाओं की निर्णय-लेने की क्षमता, घरेलू हिंसा के विरुद्ध प्रतिरोध शक्ति तथा सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाता है।

4. साहित्य समीक्षा / Review of Literature

वित्तीय समावेशन एवं महिला सशक्तिकरण पर विस्तृत अकादमिक एवं नीतिगत साहित्य उपलब्ध है। इस अनुभाग में प्रासंगिक अध्ययनों की समीक्षा की गई है जो जीविका कार्यक्रम की पृष्ठभूमि एवं विश्लेषणात्मक ढाँचे को सुदृढ़ करते हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 13, April 2026 Impact Factor: 8.2

4.1 वैश्विक एवं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

Duflo (2012) ने अपने अध्ययन में प्रमाणित किया कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और वित्तीय स्वायत्तता लैंगिक असमानता को कम करने में मदद करती है, साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार। उनका कहना है कि महिलाओं के पास आय का नियंत्रण आने से पारिवारिक कल्याण पर खर्च बहुत बढ़ गया है। इस निष्कर्ष ने स्वयं सहायता समूह आधारित माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रमों की सैद्धांतिक नींव को मज़बूत किया है।

Hashemi, Schuler और Riley (1996) ने बांग्लादेश में ग्रामीण महिलाओं पर माइक्रोफाइनेंस के प्रभावों का अध्ययन किया और पाया कि ऋण-पहुँच प्राप्त महिलाओं में घरेलू निर्णय-निर्माण, राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक गतिशीलता में स्वायत्तता काफी अधिक थी। SHG-आधारित भारतीय मॉडल में भी उनका यह निष्कर्ष लागू होता है।

Armendariz & Morduch (2010) ने अपने वृहत् तुलनात्मक अध्ययन में यह तर्क दिया कि माइक्रोफाइनेंस की सफलता केवल ऋण-वितरण पर नहीं, अपितु सामाजिक पूँजी (social capital) के निर्माण पर निर्भर करती है। जीविका का समूह-आधारित मॉडल इसी सामाजिक पूँजी को संस्थागत रूप देता है, जो महिलाओं को सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) की शक्ति प्रदान करता है।

4.2 भारतीय संदर्भ में अध्ययन

Swain और Wallentin (2009) ने आंध्र प्रदेश में SHG कार्यक्रम का अध्ययन किया और पाया कि समूह-सदस्यता ने महिलाओं को घरेलू निर्णय-प्रक्रिया में अधिक भागीदारी दिलायी। उन्हें यह भी पता चला कि राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक सशक्तिकरण के बीच एक सकारात्मक और द्विदिशिक संबंध है। NABARD (2022) की रिपोर्ट, Status of Microfinance in India, बताती है कि भारत में 1.22 करोड़ से अधिक स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनमें लगभग 14.2 करोड़ महिलाएँ हैं। वित्तीय समावेशन की दृष्टि से, इस कार्यक्रम ने वर्ष 2021-22 में ₹1,51,051 करोड़ का ऋण दिया।

Panda & Rao (2015) ने ओडिशा एवं मध्य प्रदेश में जीविका-समरूप कार्यक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बताया कि जहाँ आर्थिक सशक्तिकरण अपेक्षाकृत शीघ्र दृष्टिगोचर होता है, वहीं राजनीतिक सशक्तिकरण एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसके लिए सतत क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण आवश्यक है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 13, April 2026 Impact Factor: 8.2

4.3 बिहार एवं जीविका-केंद्रित अध्ययन

World Bank (2019) की Bihar Rural Livelihoods Project की प्रभाव-मूल्यांकन रिपोर्ट ने पुष्टि की कि जीविका से जुड़ी महिलाओं की प्रति-परिवार आय औसतन 30 से 35 प्रतिशत अधिक थी, जो गैर-सदस्य महिलाओं की तुलना में अधिक थी। इसके अलावा, समूह-सदस्य महिलाओं में कुपोषण, बाल-विवाह और घरेलू हिंसा की दरों में काफी कमी पाई गई।

Ghosh & Guha (2021) ने बिहार के गया और पूर्णिया जिलों में किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण से पता चला कि जीविका कार्यक्रम में शामिल 78 प्रतिशत महिलाओं ने अपने घरेलू बजट में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता हासिल की, जबकि 62 प्रतिशत महिलाओं ने पहली बार ग्राम पंचायत की बैठकों में सक्रिय भागीदारी की। यह अध्ययन वित्तीय समावेशन और राजनीतिक सहभागिता के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। यह अध्ययन वित्तीय समावेशन एवं राजनीतिक सहभागिता के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है।

Kumar & Singh (2020) ने NITI Aayog की SDG India Index के संदर्भ में बिहार की प्रगति का विश्लेषण करते हुए पाया कि 2015 से 2020 के बीच SDG-5 (लैंगिक समानता) के सूचकांक में 8 अंकों का सुधार हुआ, जो जीविका कार्यक्रम से हुआ था। उन्होंने इसे सीधे वित्तीय समावेशन की दर से जोड़ा। विकास मंत्रालय (2023 की वार्षिक रिपोर्ट) में बताया गया है कि DAY-NRLM (Deendayal Antyodaya Yojana—National Rural Livelihoods Mission) के अंतर्गत जीविका को राज्य-स्तरीय आदर्श कार्यान्वयन एजेंसी घोषित किया गया है। रिपोर्ट मानती है कि जीविका का SHG-ग्राम संगठन-क्लस्टर स्तरीय संघ का त्रिस्तरीय ढाँचा ग्रामीण शासन और स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने में सफल रहा है।

Banerjee et al. (2015) के रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल (RCT) अध्ययन ने माइक्रोफाइनेंस के प्रभाव को छह देशों (भारत भी शामिल है) में देखा। उन्हें पता चला कि माइक्रोफाइनेंस का प्रभाव सिर्फ गरीबी उन्मूलन में सीमित है, लेकिन जब इसे कौशल प्रशिक्षण, बाजार-लिंकेज और सामाजिक जागरूकता अभियानों, जैसे जीविका करना, के साथ जोड़ा जाता है, तो महिला सशक्तिकरण के परिणाम बहुआयामी और टिकाऊ होते हैं।

Dreze & Sen (2013) ने भारत में विकास और वंचना के बारे में कहा कि बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं की निम्न स्थिति का मूल कारण ऐतिहासिक संरचनात्मक असमानताएँ हैं, जो संस्थागत माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रमों द्वारा ही दूर की जा सकती हैं। यह विचार जीविका की नीतिगत संरचना को सैद्धांतिक मान्यता देता है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 13, April 2026 Impact Factor: 8.2

5. शोध-अंतराल एवं उद्देश्य / Research Gap and Objectives

उपर्युक्त साहित्य समीक्षा से स्पष्ट है कि वित्तीय समावेशन एवं महिला सशक्तिकरण पर व्यापक अध्ययन उपलब्ध हैं, परंतु बिहार में जीविका कार्यक्रम के संदर्भ में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण के त्रिआयामी विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित अध्ययनों का अभाव है। विशेष रूप से, वित्तीय समावेशन एवं राजनीतिक सहभागिता के अंतर्संबंध पर द्वितीयक डेटा आधारित विश्लेषणात्मक शोध की आवश्यकता बनी हुई है।

प्रस्तुत शोध के तीन प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. वित्तीय समावेशन की अवधारणा तथा ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी भूमिका का विश्लेषण करना।
2. बिहार में JEEViKA कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण का मूल्यांकन करना।
3. वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं निर्णय-निर्माण क्षमता पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना।

6. डेटा स्रोत एवं शोध-पद्धति / Data Sources and Methodology

यह शोध-पत्र पूर्णतः द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। डेटा संकलन के लिए NABARD Annual Reports (2018-2023), World Bank Project Reports, Government of Bihar — JEEViKA Annual Reports, Ministry of Rural Development Reports, NITI Aayog SDG India Index Reports, RBI Annual Reports on Financial Inclusion तथा UGC CARE / Scopus अनुक्रमित पत्रिकाओं में प्रकाशित शोधपत्रों का उपयोग किया गया है।

शोध-पद्धति में वर्णनात्मक विश्लेषण (Descriptive Analysis), नीति-विश्लेषण (Policy Analysis) तथा तुलनात्मक एवं वैचारिक विश्लेषण (Comparative & Conceptual Analysis) का समन्वित उपयोग किया गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों की त्रिभुज-प्रमाणिकता (Triangulation) सुनिश्चित की गई है ताकि निष्कर्षों की विश्वसनीयता बनी रहे।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 13, April 2026 Impact Factor: 8.2

7. जीविका की भूमिका / Role of JEEViKA in Financial Inclusion

जीविका (JEEViKA) — Bihar Rural Livelihoods Project — की स्थापना 2006 में Government of Bihar एवं World Bank के संयुक्त सहयोग से हुई। 2015 में इसे DAY-NRLM के अंतर्गत राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी (SRLM) के रूप में पुनर्गठित किया गया। Government of Bihar (2023) के आंकड़ों के अनुसार, जीविका के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित उपलब्धियाँ दर्ज की गई हैं:

- 38 ज़िलों में 1.30 लाख से अधिक ग्राम संगठन (Village Organisations) कार्यशील हैं।
- प्रदेश में 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह (SHGs) सक्रिय हैं, जिनमें 1.2 करोड़ से अधिक महिला सदस्य हैं।
- क्लस्टर स्तरीय संघ (CLF) के माध्यम से बैंक-लिंकेज तथा सामुदायिक निवेश निधि (CIF) का वितरण किया जाता है।
- वर्ष 2022-23 में ₹18,000 करोड़ से अधिक का ऋण-वितरण SHG-बैंक लिंकेज के माध्यम से हुआ।
- NABARD (2022) के अनुसार बिहार में SHG-बैंक लिंकेज की ऋण-पुनर्भुगतान दर 95 प्रतिशत से अधिक रही।

जीविका की संस्थागत संरचना त्रिस्तरीय है: (i) स्वयं सहायता समूह (SHG) → (ii) ग्राम संगठन (VO) → (iii) क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF)। यह संरचना महिलाओं को न केवल वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती है, अपितु उन्हें संस्थागत प्रशासन, सामूहिक जवाबदेही तथा सामाजिक ऑडिट जैसे लोकतांत्रिक अभ्यासों से भी जोड़ती है (Ministry of Rural Development, 2022)।

8. महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव / Impact on Women Empowerment

8.1 आर्थिक सशक्तिकरण / Economic Empowerment

ग्रामीण महिलाओं की आय, बचत और ऋण-पहुँच के माध्यम से जीवन कार्यक्रम ने आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। World Bank (2019) के प्रभाव-मूल्यांकन के अनुसार, जीविका-सदस्य परिवारों की वार्षिक आय 28 से 33 प्रतिशत बढ़ी। NABARD (2022) की रिपोर्ट के अनुसार, 2010 में SHG सदस्य महिलाओं की औसत बचत राशि ₹800 थी, लेकिन आज ₹4,200 प्रति वर्ष हो गई है। जीविका ने महिलाओं को कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प से जोड़ा है। Government of Bihar

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 13, April 2026 Impact Factor: 8.2

(2023) के अनुसार, 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने 'जीविका दीदी' उत्पाद ब्रांड के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँचाया है। सामुदायिक निवेश निधि (CIF) ने महिलाओं को साहूकारों से मुक्ति दिलाने में भी प्रभावशाली भूमिका निभाई है (NITI Aayog, 2021)।

8.2 सामाजिक सशक्तिकरण / Social Empowerment

वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होने से ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। Bihar सरकार (2023) की रिपोर्ट बताती है कि जीविका-सदस्य महिलाओं में बाल-विवाह की दर में 18 प्रतिशत की कमी, बालिका शिक्षा नामांकन में 12 प्रतिशत की वृद्धि और संस्थागत प्रसव में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

NITI Aayog (2021) की रिपोर्ट के अनुसार, जीविका का 'महिला संवाद' और 'स्वास्थ्य दीदी' कार्यक्रम मातृ-शिशु पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं को जागरूक करने में सफल रहे हैं। आर्थिक स्वतंत्रता ने महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ बोलने में भी सक्षम बनाया है, जो कैबीर (1999) के 'एजेंसी' सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से प्रमाणित करता है।

8.3 राजनीतिक सहभागिता / Political Participation

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का क्षेत्र जीवन पर सबसे व्यापक प्रभाव डालता है। ग्राम संगठन के प्रशासनिक कार्य, क्लस्टर फेडरेशन की समितियाँ और SHG की नियमित बैठकें महिलाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण देती हैं (Ministry of Rural Development, 2023)। Bihar Government (2023) के आंकड़ों के अनुसार, 2021 के बिहार पंचायत चुनावों में जीविका-सदस्य महिलाओं में से 52,000 से अधिक महिलाएँ विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में चुनाव जीतीं। 2016 की तुलना में यह आंकड़ा 38% बढ़ा। RBI (2022) की Financial Inclusion Index रिपोर्ट भी स्वीकार करती है कि राज्यों में SHG-घनत्व अधिक है, वहाँ महिलाओं की जन-प्रतिनिधित्व और मतदान-सहभागिता भी अधिक है।

Swain & Wallentin (2009) के निष्कर्षों के अनुरूप, बिहार में भी देखा गया है कि आर्थिक सशक्तिकरण एवं राजनीतिक भागीदारी के बीच का संबंध रैखिक नहीं, अपितु पारस्परिक एवं संवर्धनशील है। वित्तीय

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 13, April 2026 Impact Factor: 8.2

आत्मनिर्भरता महिलाओं में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है, जो उन्हें सार्वजनिक संवाद एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है।

8.4 लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी/ Women's participation in the Lok Sabha

महिलाओं की लोकसभा में भागीदारी महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण संकेत है क्योंकि यह उनकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने में भूमिका को दर्शाती है। स्वतंत्रता के बाद से महिलाओं की संख्या धीरे-धीरे बढ़ी है, लेकिन अभी भी पर्याप्त है। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 2019 में लगभग 14% रही, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है, लेकिन लैंगिक समानता से कम है (India Election Commission, 2019) महिलाओं की अधिक भागीदारी से सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक विषयों को नीति-निर्माण में अधिक प्राथमिकता मिलती है (Krook & O'Brien, 2012)। यही कारण है कि लोकसभा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से उनका राजनीतिक सशक्तिकरण सुदृढ़ होता है, जो उन्हें व्यापक सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण देता है।

9. विवेचन एवं नीतिगत निहितार्थ / Discussion and Policy Implications

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जीविका ने बिहार में वित्तीय समावेशन को महिला सशक्तिकरण के व्यापक एजेंडे से जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। तथापि कुछ चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं जिनका समाधान नीति-निर्माताओं को करना होगा।

प्रथम, ऋण मिलने के बावजूद वित्तीय साक्षरता की कमी एक बाधा बन गई है। NABARD (2022) के अनुसार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में SHG सदस्यों में से केवल 42 प्रतिशत महिलाएँ बैंक स्टेटमेंट पढ़ सकती हैं। इसलिए जीवन की गतिविधियों में वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों को व्यापक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। द्वितीय, डिजिटल वित्तीय समावेशन धीमा है। RBI (2022) की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में ग्रामीण महिलाओं का स्मार्टफोन का उपयोग केवल 28 प्रतिशत है, जो डिजिटल बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच को सीमित करता है। PM-Jan Dhan-Aadhaar-Mobile (JAM Trinity) को जीवन प्रणाली से एकीकृत करना चाहिए (NITI Aayog, 2021)।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 13, April 2026 Impact Factor: 8.2

तृतीय,संस्थागत समर्थन राजनीतिक सशक्तिकरण को चाहिए। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को 'Proxy Representation' की समस्या से बचाने के लिए क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण की जरूरत है। केंद्रीय कृषि विकाश विभाग (2023) ने इस दिशा में एक "जन-प्रतिनिधित्व प्रशिक्षण मॉड्यूल" बनाया है, लेकिन इसे और अधिक व्यापक रूप से लागू किया जाना चाहिए। World Bank (2021) ने कहा कि अगर महिलाओं की आय वृद्धि दीर्घकालीन और निरंतर होनी चाहिए, तो जीविका कार्यक्रम को बाजार-लिंकेज, कृषि-प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के साथ अधिक गहनता से एकीकृत किया जाना चाहिए।

10. निष्कर्ष / Conclusion

यह अध्ययन बताता है कि जीविका (JEEViKA) ने बिहार में वित्तीय समावेशन को महिला सशक्तिकरण का आधार बनाकर ग्रामीण विकास में नए आयाम खोले हैं। SHG-आधारित संस्थागत ढांचे ने महिलाओं को बचत, ऋण और बीमा जैसे वित्तीय सुविधाएं दी हैं, साथ ही उनके सामाजिक स्तर में सुधार और राजनीतिक चेतना का विकास किया है।

शोध के तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि: (i) वित्तीय समावेशन ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावशाली उपकरण है; (ii) जीविका कार्यक्रम ने बिहार में महिलाओं की आय, बचत, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण सुधार लाए हैं; तथा (iii) वित्तीय समावेशन एवं राजनीतिक भागीदारी के बीच एक सकारात्मक, पारस्परिक एवं संवर्धनशील संबंध विद्यमान है जिसे जीविका के अनुभव से प्रमाणित किया जा सकता है।

भविष्य में महत्वपूर्ण डेटा-आधारित अध्ययनों की जरूरत होगी जो वित्तीय समावेशन और राजनीतिक सशक्तिकरण के कारण-प्रभाव संबंध (Causal Relationship) की व्यापक जांच करें। विभिन्न पिछड़े राज्यों के लिए जीवन का मॉडल अनुकरणीय है, लेकिन इसे सफलतापूर्वक अनुकरण करने के लिए स्थानीय सांस्कृतिक और संरचनात्मक पहलुओं का ध्यान रखना होगा।

संदर्भ-सूची / References

1. United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations.

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 13, April 2026
Impact Factor: 8.2

2. Reserve Bank of India. (2022). Report on financial inclusion 2021–22. Reserve Bank of India.
3. NITI Aayog. (2021). SDG India index and dashboard 2020–21. Government of India.
4. Armendariz, B., & Morduch, J. (2010). The economics of microfinance (2nd ed.). MIT Press.
5. Banerjee, A., Duflo, E., Glennerster, R., & Kinnan, C. (2015). The miracle of microfinance? Evidence from a randomized evaluation. American Economic Journal: Applied Economics, 7(1), 22–53. https://doi.org/10.1257/app.20130533
6. Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.
7. Dreze, J., & Sen, A. (2013). An uncertain glory: India and its contradictions. Princeton University Press.
8. Duflo, E. (2012). Women empowerment and economic development. Journal of Economic Literature, 50(4), 1051–1079. https://doi.org/10.1257/jel.50.4.1051.
9. Ghosh, S., & Guha, A. (2021). Financial inclusion and women's empowerment: Evidence from JEEViKA in Bihar. Indian Journal of Rural Development, 40(3), 112–129.
10. Government of Bihar. (2023). JEEViKA annual report 2022–23: Bihar rural livelihoods project. Bihar Rural Livelihoods Promotion Society.
11. Hashemi, S. M., Schuler, S. R., & Riley, A. P. (1996). Rural credit programs and women's empowerment in Bangladesh. World Development, 24(4), 635–653. https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00159-A
12. Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. Development and Change, 30(3), 435–464. https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125.
13. Kumar, R., & Singh, P. (2020). SDG progress and JEEViKA: Analysing gender development in Bihar. Journal of Development Policy and Practice, 5(2), 189–207.
14. Ministry of Rural Development. (2022). DAY-NRLM annual report 2021–22. Government of India.
15. Ministry of Rural Development. (2023). DAY-NRLM annual report 2022–23. Government of India.

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 13, April 2026
Impact Factor: 8.2

16. NABARD. (2022). Status of microfinance in India 2021–22. National Bank for Agriculture and Rural Development.
17. NITI Aayog. (2020). SDG India index and dashboard 2019–20. Government of India.
18. Panda, S., & Rao, M. (2015). Women empowerment through microfinance: A comparative study of Odisha and Madhya Pradesh. Social Change, 45(1), 78–95. https://doi.org/10.1177/0049085715569778.
19. Rangarajan, C. (2008). Report of the committee on financial inclusion. Ministry of Finance, Government of India.
20. Reserve Bank of India. (2008). Report on currency and finance 2006–08: An overview of financial inclusion. RBI Publications.
21. Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
22. Election Commission of India. (2019). *Statistical report on general elections, 2019*. Election Commission of India.
23. Krook, M. L., & O'Brien, D. Z. (2012). All the president's men? The appointment of female cabinet ministers worldwide. *The Journal of Politics, 74*(3), 840–855.
24. Swain, R. B., & Wallentin, F. Y. (2009). Does microfinance empower women? Evidence from self-help groups in India. International Review of Applied Economics, 23(5), 541–556. https://doi.org/10.1080/02692170903007540
25. World Bank. (2019). Bihar rural livelihoods project: Implementation completion and results report. World Bank Group.
26. World Bank. (2021). Financial inclusion overview. World Bank Group. https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview.